डाक पंजीयन क्रमांक - म.प्र./भोपाल/4-357/2024-26

मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष
सहकारी समितियां एक बेहतर दुनिया का निर्माण करती हैं

मध्यप्रदेश सहकारी समाचार

मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ भोपाल का प्रकाशन

Website : www.mpscu.in
E-mail : rajyasanghbpl@yahoo.co.in

हिन्दी/पाक्षिक
प्रकाशन दिनांक 1 सितम्बर, 2025, डिस्पेच दिनांक 1 सितम्बर, 2025

| वर्ष 69 | अंक 07 | भोपाल | 1 सितम्बर, 2025 | पृष्ठ 8 | एक प्रति 7 रु. | वार्षिक शुल्क 150/- | आजीवन शुल्क 1500/- |

आत्मनिर्भर भारत : एक मजबूत और विकसित भारत की नींव

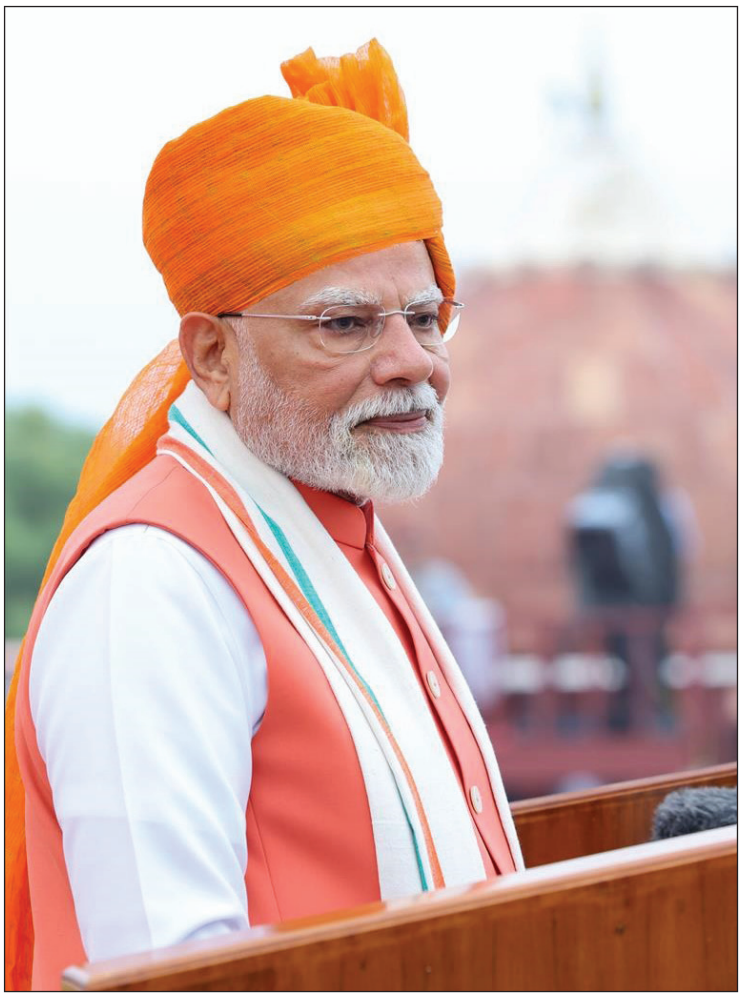

नई दिल्ली। 79वें स्वतंत्रता दिवस पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रक्षा, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, अंतरिक्ष और विनिर्माण के क्षेत्र में हुई भारत की प्रगति का हवाला देते हुए, आत्मनिर्भर भारत को विकसित भारत के प्रमुख आधारभूत सिद्धांतों में से एक बताया। ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि रणनीतिक स्वायत्तता और स्वदेशी क्षमताएँ, खतरों से निर्णायक रूप से निपटने, आत्मनिर्भरता को राष्ट्रीय शक्ति, सम्मान और 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का आधार बनाने के लिए बेहद अहम हैं।

आत्मनिर्भर भारत : प्रधानमंत्री श्री मोदी के संबोधन के मुख्य बिंदू

1. **रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और ऑपरेशन सिंदूर:** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत की रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का एक उदाहरण बताया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वदेशी क्षमताएँ, जिनमें भारत में निर्मित हथियार भी शामिल हैं, भारत को निर्णायक और स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम बनाती हैं, जिससे यह साबित होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी निर्भरता के भरोसा नहीं रह सकती।
2. **जेट इंजन में आत्मनिर्भरता:** उन्होंने भारतीय नवप्रवर्तकों और युवाओं से भारत में ही जेट इंजन विकसित करने का आग्रह किया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य की रक्षा तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी और आत्मनिर्भर हो।
3. **सेमीकंडक्टर और उच्च-तकनीकी नेतृत्व:** भारत 2025 के अंत तक मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करेगा, जो अहम तकनीकी क्षेत्रों में देश की बढ़ती ताकत को दर्शाता है। उन्होंने वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए एआई, साइबर सुरक्षा, डीप-टेक और ऑपरेटिंग सिस्टम में नवाचार पर ज़ोर दिया।
4. **अंतरिक्ष क्षेत्र की स्वतंत्रता:**
   - ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की उल्लेखनीय उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वाकांक्षी योजनाओं का एलान किया, जिससे स्वदेशी अंतरिक्ष क्षमताओं के एक नए युग का संकेत मिलता है।
   - उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 300 से ज़्यादा स्टार्टअप, उपग्रहों, अन्वेषण और अत्याधुनिक अंतरिक्ष तकनीकों में सक्रिय रूप से नए विचारों पर काम कर रहे हैं, जिससे यह साफ होता है कि भारत न केवल अंतरिक्ष विज्ञान और अन्वेषण में भाग ले रहा है, बल्कि वैश्विक स्तर पर अग्रणी भूमिका भी निभा रहा है।
5. **स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा**
   - प्रधानमंत्री मोदी ने ऊर्जा स्वतंत्रता के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि युवाओं के उज्ज्वल भविष्य और किसानों के कल्याण के लिए यह ज़रूरी है और यह किया जाएगा।
   - उन्होंने एलान किया कि एक तरफ जहाँ दुनिया ग्लोबल वार्मिंग पर बहस कर रही है, वहीं भारत ने 2030 तक 50% स्वच्छ ऊर्जा हासिल करने का संकल्प लिया, फिर भी, लोगों की प्रतिबद्धता की बदौलत, यह लक्ष्य 2025 तक पूरा हो गया।
   - सौर, परमाणु, जलविद्युत और हाइड्रोजन ऊर्जा को और उन्नत किया गया है, जो ऊर्जा स्वतंत्रता की दिशा में एक अहम कदम है।
   - प्रधानमंत्री श्री मोदी ने निजी क्षेत्र की भागीदारी के ज़रिए परमाणु ऊर्जा के विस्तार पर भारत के फोकस पर बात की। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 10 नए परमाणु रिएक्टर चालू हैं और भारत की स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक, राष्ट्र का लक्ष्य, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मज़बूत करते हुए और सतत् विकास को बढ़ावा देते हुए, अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को दस गुना बढ़ाना है।
6. **राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन:** ऊर्जा, उद्योग और रक्षा के लिए ज़रुरी संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, भारत ने राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन की शुरूआत की है, जिसके तहत 1,200 स्थलों की खोज की जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इन खनिजों पर नियंत्रण से रणनीतिक स्वायत्तता मज़बूत होती है, जिससे भारत के औद्योगिक और रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर बने रहते हैं।
7. **राष्ट्रीय गहरे जल अन्वेषण मिशन:** भारत अपने गहरे जल ऊर्जा संसाधनों का दोहन करेगा, ऊर्जा आत्मनिर्भरता को मज़बूत करेगा और विदेशी ईंधन आयात पर निर्भरता कम करेगा।
8. **कृषि आत्मनिर्भरता और उर्वरक:** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने किसानों को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की रक्षा के लिए, घरेलू स्तर पर उर्वरकों के उत्पादन की तत्काल ज़रुरत पर बल दिया। आयात पर निर्भरता कम करने से, देश का कृषि क्षेत्र स्वतंत्र रूप से फलता-फूलता रहेगा, किसानों का कल्याण होगा और भारत की आर्थिक संप्रभुता मजबूत होगी।
9. **डिजिटल संप्रभुता और स्वदेशी प्लेटफ़ॉर्म:** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने युवाओं से भारत के अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म और डिजिटल बुनियादी ढाँचा विकसित करने का आह्वान किया, जिससे संचार, डेटा और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र सुरक्षित और स्वतंत्र रहें और भारत की डिजिटल स्वायत्तता को मज़बूत किया जा सके।
10. **दवाओं और नवाचार में आत्मनिर्भरता:** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने "दुनिया की फार्मेसी" के रूप में भारत की ताकत पर प्रकाश डाला और अनुसंधान एवं विकास में और अधिक निवेश की तत्काल ज़रुरत पर बल दिया। उन्होंने पूछा, "क्या हमें मानवता के कल्याण के लिए सर्वोत्तम और सबसे सस्ती दवाइयाँ उपलब्ध नहीं करवानी चाहिए?"
    - उन्होंने घरेलू दवा नवाचारों में भारत की बढ़ती ताकत पर प्रकाश डाला और पूरी तरह से भारत में ही नई दवाइयाँ, टीके और जीवन रक्षक उपचार विकसित करने की ज़रुरत पर बल दिया।
    - भारत की कोविड-19 प्रतिक्रिया से प्रेरणा लेते हुए, जहाँ स्वदेशी टीकों और को विन जैसे मंचों ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई, उन्होंने राष्ट्र से नवाचार की इस भावना का विस्तार करने का आग्रह किया।
    - उन्होंने शोधकर्ताओं और उद्यमियों से नई दवाओं और चिकित्सा प्रौद्योगिकियों के लिए पेटेंट हासिल करने का आह्वान किया, ताकि भारत न केवल अपनी स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी ज़रुरतों को पूरा कर सके, बल्कि वैश्विक कल्याण में भी योगदान दे तथा खुद को चिकित्सा आत्मनिर्भरता और नवाचार के केंद्र के रूप में स्थापित भी करे।
11. **स्वदेशी का समर्थन:** प्रधानमंत्री श्री मोदी ने नागरिकों और दुकानदारों से "वोकल फॉर लोकल" पहल के तहत भारत में निर्मित वस्तुओं का समर्थन करने का आग्रह किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि स्वदेशी उत्पादों की शुरूआत गर्व और शक्ति की भावना से होनी चाहिए, न कि मजबूरी से। उन्होंने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने, उद्यमशीलता को समर्थन देने और भारत के आर्थिक और औद्योगिक आधार को मजबूत करने के लिए दुकानों के बाहर "स्वदेशी" बोर्ड जैसे दृश्य प्रचार का आह्वान किया।
12. **मिशन सुदर्शन चक्र:** परंपरा का सम्मान और रक्षा को मजबूत करना: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने "मिशन सुदर्शन चक्र" के शुभारंभ का भी एलान किया, जिसका मकसद दुश्मन की रक्षा घुसपैठ को बेअसर करना और भारत की आक्रामक क्षमताओं को बढ़ाना है।

उन्होंने इस मिशन को पौराणिक श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से जोड़ा और इस बात पर प्रकाश डाला कि कैसे भारत आधुनिक रक्षा नवाचारों में मार्गदर्शन के लिए, अपनी समृद्ध सांस्कृतिक और पौराणिक विरासत से प्रेरणा लेता है। यह मिशन रणनीतिक स्वायत्तता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है, जो किसी भी खतरे का त्वरित, सटीक और शक्तिशाली जवाब देने में सक्षम है।

प्रदेश में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई स्वतंत्रता दिवस की वर्षगांठ

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के प्रदेश की जनता के नाम संदेश का जिला मुख्यालय के समारोह में हुआ लाइव-प्रसारण

भोपाल : प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस की 79वीं दिवस हर्षोल्लास और देशभक्ति की भावना के साथ मनाई गई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउण्ड पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में ध्वजारोहण कर भव्य परैड की सलामी ली। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश की जनता के नाम संदेश में मध्यप्रदेश की प्रगति एवं उपलब्धियों की जानकारी भी दी। प्रदेश में पहली बार मुख्यमंत्री के संदेश का सीधा प्रसारण जिला मुख्यालयों पर आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में किया गया। सभी जिला मुख्यालयों पर ध्वजारोहण, आकर्षक परेड के साथ राष्ट्रभक्ति से ओत-प्रोत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित हुए। साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी - कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया।

किसने कहाँ किया ध्वजारोहण

उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने जबलपुर और उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने शहडोल में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। जनजातीय कार्य, लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास मंत्री डॉ. कुंवर विजय शाह रतलाम, नगरीय विकास एवं आवास, संसदीय कार्य मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय धार, पंचायत, ग्रामीण विकास एवं श्रम मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल भिण्ड, लोक निर्माण मंत्री श्री राकेश सिंह नर्मदापुरम, राजस्व मंत्री श्री करन सिंह वर्मा मुरैना, स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह बालाघाट, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री श्रीमती सम्पतिया उइके मंडला, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट बुरहानपुर, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना दतिया, महिला बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया मंदसौर, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत नरसिंहपुर, खेल, युवा कल्याण एवं सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग खरगोन, सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण, उद्यानिकी तथा खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री श्री नारायण सिंह कुशवाह ग्वालियर, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान अलीराजपुर, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर शिवपुरी और नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री राकेश शुक्ला श्योपुर, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप राजगढ़, उच्च शिक्षा, आयुष एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री इन्दर सिंह परमार दमोह में ध्वजारोहण किया और परेड की सलामी ली।

पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक, विमुक्त घुमन्तु और अर्द्धघुमन्तु कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती कृष्णा गौर सीहोर, संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और धर्मस्व राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र भाव सिंह लोधी खंडवा, राज्य कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री दिलीप जायसवाल सीधी, कौशल विकास एवं रोजगार राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री गौतम टेटवाल बड़वानी, पशुपालन एवं डेयरी राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल मउगंज, मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री नारायण सिंह पंवार रायसेन, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्यमंत्री श्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल बैतूल, नगरीय विकास एवं आवास राज्यमंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी डिंडोरी, वन, पर्यावरण राज्यमंत्री श्री दिलीप अहिरवार अनूपपुर और पंचायत और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री श्रीमती राधा सिंह सिंगरौली में ध्वजारोहण कर परैड की सलामी ली।

इंदौर, झाबुआ, पन्ना, टीकमगढ़, निवाड़ी, सागर, उज्जैन, देवास, विदिशा, शाजापुर, आगर मालवा, हरदा, नीमच, गुना, अशोकनगर, कटनी, छिंदवाड़ा, सिवनी, रीवा, मैहर, पांढुर्ना, छतरपुर, सतना एवं उमरिया जिले में कलेक्टर ने ध्वजारोहण कर परैड की सलामी ली।

किसानों के कल्याण और पूरी अर्थव्यवस्था को लाभान्वित करने के लिए निरंतर बढ़ता रहे सिंचाई क्षेत्र : मुख्यमंत्री

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की समृद्धि के साथ प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सकारात्मक परिवर्तन के लिए सिंचाई क्षेत्र का निरंतर विस्तार आवश्यक है। इसके लिए जल संसाधन विभाग और सभी संबंधित एजेंसियां तेजी से कार्य करें। वर्तमान में शासकीय स्रोतों से प्रदेश में सिंचाई प्रतिशत 52 लाख हेक्टेयर से अधिक हो चुका है। इसे शीघ्र ही दोगुना करने का लक्ष्य ध्यान में रखकर कार्य किया जाए जिससे आने वाले 3 वर्ष में प्रदेश में 100 लाख हेक्टेयर में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हो जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि कृषि के साथ ही उद्योग क्षेत्र में पानी देने, पेयजल प्रबंध और ऊर्जा उत्पादन में जल का उपयोग जल संसाधन विभाग के स्रोतों से हो रहा है। सिंचाई के 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लक्ष्य के अनुसार जल संसाधनों के समुचित उपयोग को पूरी प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान विभिन्न परियोजनाओं से बढ़ रहे सिंचाई क्षेत्र की जानकारी भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अंतर्राज्यीय नदी जोड़ो परियोजनाओं जैसे केन-बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना, संशोधित पार्वती-काली-सिंध चंबल लिंक परियोजना को अति उपयोगी बताते हुए कहा कि इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से प्रदेश के लगभग आधे जिलों की तस्वीर बदल जाएगी। राज्य के अंदर भी नदी जोड़ो परियोजनाओं के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य प्रारंभ कर लाभ प्राप्त किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नदियों को जोड़ने का स्वप्न भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल ने देखा जिसे प्रधानमंत्री श्री मोदी साकार कर हैं। वर्तमान में भारत सरकार द्वारा ऐसी परियोजनाओं के लिए 90% राशि देने का लाभकारी प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुसार राज्यों की ऐसी पहल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। नदी जोड़ो परियोजनाओं के कार्य जैसे-जैसे क्रियान्वित होंगे, सिंचित क्षेत्र बढ़ेगा, साथ ही खुशहाली भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल संसाधन विभाग की ओर से राज्य के अंदर नदी जोड़ो प्रकल्पों की संभावनाओं का सर्वेक्षण और अध्ययन कर प्रतिवेदन तैयार किया जाए। केन्द्र सरकार को ऐसे प्रस्ताव भेजकर स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि रबी 2023-24 में प्रदेश में सिंचित रकबा 44.56 लाख हेक्टेयर था जो रबी 2025-26 में बढ़कर 52.06 हो गया है। इस तरह बीते डेढ़ वर्ष में प्रदेश के सिंचाई क्षेत्र में 7.50 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। इसमें जल संसाधन विभाग द्वारा 2.39 और नर्मदा घाटी विकास विभाग 5.11 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने में सफलता प्राप्त की गई है। बताया गया कि प्रदेश में आगामी पांच वर्ष में 200 करोड़ से अधिक लागत की 38 सिंचाई परियोजनाएं पूरी हो जाएंगी, जिसके फलस्वरूप 17 लाख 33 हजार 791 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होगा। इस वर्ष 2 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई क्षेत्र बढ़ेगा, जो मोहनपुरा बांयीतट परियोजना जिला राजगढ़, चंदेरी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना जिला अशोकनगर, पंचमनगर सिंचाई परियोजना जिला दमोह एवं सागर, त्योंथर बहाव योजना जिला रीवा और घोघरी मध्यम परियोजना जिला बैतूल के माध्यम से संभव होगा।

बैठक में जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास डॉ. राजेश राजौरा सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

पशुपालन से किसानों की बढ़ेगी आय, बनेंगे आत्मनिर्भर

भोपाल :प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें पशुपालन गतिविधियों से जोड़ा जा रहा है। सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दे रही है। पशुपालन से किसानों की आय बढ़ेगी और वे आत्मनिर्भर होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का यह हमारा संकल्प है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन निरंतर बढ़े और वर्ष 2028 तक प्रदेश को देश की 'मिल्क कैपिटल' बनाया जाये। गो- संरक्षण और गो-संवर्धन सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए निरंतर कार्य किये जा रहे हैं।

प्रदेश में पशुपालन विभाग को गो-पालन विभाग का नाम दिया गया है। प्रदेश में देश के कुल दुग्ध उत्पादन का 9% होता है, जिसे 20% तक ले जाने का सरकार का लक्ष्य है। प्रदेश में गोवंश के लिए आहार की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रतिमाह दी जाने वाली राशि को रु.20 से बढ़कर रु.40 कर दिया गया है। 'हर घर गोकुल' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश में 946 नई दुग्ध सहकारी समितियों का गठन किया गया है। मुख्यमंत्री वृंदावन ग्राम योजना में प्रदेश के ग्रामों को आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। दुग्ध उत्पादन और ग्रामीण आजीविका को बढ़ाने के लिए प्रत्येक जनपद में एक वृंदावन ग्राम बनाया जा रहा है।

दुग्ध उत्पादन से अधिक आय के लिए मध्यप्रदेश दुग्ध संघ के सांची ब्रांड को अधिक लोकप्रिय बनाया जा रहा है, इसके लिए नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से करार भी किया गया है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध उत्पादों की बेहतर ब्राडिंग, गोवंश की समुचित देखभाल, वेटनरी क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और उन्नत अधोसंरचना स्थापित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का हरसंभव लाभ लिया जा रहा है। वर्ष 2030 तक प्रदेश के 26 हजार गांवों तक डेयरी नेटवर्क का विस्तार सुनिश्चित किया जाना है। इससे 52 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन होगा। बढ़े हुए दुग्ध संकलन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित की जाएगी। प्रदेश में निर्मित होने वाले दुग्ध उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर पर ब्राडिंग सुनिश्चित की जाएगी।

प्रदेश में पशुपालन और डेयरी विकास के लिए सरकार द्वारा नई योजनाएं शुरू की गई हैं। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना में पशुपालक को 25 दुधारू पशु गाय, संकर गाय, भैंस की इकाई प्रदान की जाएगी। इस इकाई की लागत 36 से 42 लाख रुपए के बीच रहेगी। योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितग्राहियों के लिए 33 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के

लिए 25% अनुदान की व्यवस्था की गई है। सरकार अब सिर्फ भैंस का नहीं गाय का दूध भी खरीदेगी। गाय के दूध की खरीद की कीमत बढ़ाई जाएगी। प्रदेश में "स्वावलंबी गो-शालाओं की स्थापना नीति 2025" भी लागू की गई है। इसके अंतर्गत नगरीय क्षेत्र में उपलब्ध गो वंश के आश्रय एवं भरण पोषण के लिए 05 हजार गो-वंश से अधिक की क्षमता वाली वृहद गो-शालाएं नगर निगम ग्वालियर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और जबलपुर में स्थापित की जा रही हैं।

गो-संरक्षण एवं संवर्धन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश देश का अग्रणी राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु योजना, कामधेनु निवास योजना, मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम, नस्ल सुधार कार्यक्रम के साथ ही विभिन्न केंद्रीय योजनाओं का प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में न केवल गोवंश का समुचित पालन-पोषण किया जा रहा है, अपितु दुग्ध उत्पादन में भी निरंतर वृद्धि हो रही है।

प्रदेश में स्वाबलंबी गो-शालाओं की स्थापना नीति पर तेज गति से कार्य किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 28 स्थान चिन्हित किए गए हैं तथा 8 स्वयं सेवी संस्थाओं को भूमि भी आबंटित भी की जा चुकी है। योजना में 5000 एवं अधिक गो-वंश के पालन पर शासन की ओर से 130 एकड़ तक भूमि आवंटित किए जाने का प्रावधान है। गो-शालाओं के लिए चारा-भूसा अनुदान योजना के अंतर्गत इस वित्त वर्ष में विभिन्न गो-शालाओं को 133.35 करोड रुपए दिए गए हैं। गत वर्ष इस योजना में 270.40 करोड़ रुपए गो-शालाओं को अनुदान के रूप में दिए गए थे।

प्रदेश में गो संवर्धन बोर्ड के अंतर्गत 2942 गो-शालाएं पंजीकृत हैं, जिनमें 2828 गो-शालाएं संचालित हैं। इन गो-शालाओं में 04 लाख 22 हजार गो-वंश का पालन-पोषण किया जा रहा है। गत एक वर्ष में प्रदेश में कुल 623 गौशालाएं पंजीकृत हुई हैं, जिनमें 596 गौशालाएं मनरेगा योजना के अंतर्गत बनाई गई हैं तथा 27 का संचालन स्वयंसेवी संस्थाएं कर रही हैं।

प्रदेश में अति पिछड़े बैगा, सहरिया और भारिया जनजाति के पशुपालकों के लिए प्रदेश के 14 जिलों में मुख्यमंत्री दुधारु पशु योजना संचालित की जा रही है, जिसके अंतर्गत सरकार द्वारा 90% अनुदान पर प्रत्येक हितग्राही को दो-दो मुर्रा भैंस/ गाय प्रदान की जाती है। योजना में गत वर्ष 660 के विरुद्ध 639 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया था तथा इस वर्ष 483 को पशु प्रदान किए जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस कार्यक्रम प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में सीहोर विदिशा तथा रायसेन जिलों में चलाया जा रहा है। केंद्र सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कुल 1500 " मैत्री" की स्थापना के लिए 12 करोड़ 15 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है। प्रदेश में कृत्रिम गर्भाधान के माध्यम से पशु नस्ल सुधार के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है।

गो-डॉउन में ही उपार्जन केन्द्र बनाने को दी जायेगी प्राथमिकता : अपर मुख्य सचिव

प्रोक्योरमेंट रिफार्म पर हुई स्टेट लेवल वर्कशॉप

भोपाल :गो-डॉउन में ही उपार्जन केन्द्र बनाने को प्राथमिकता दी जायेगी। जिससे उपार्जित अनाज के परिवहन में लगने वाला खर्च बच सके। अपर मुख्य सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने यह बात प्रोक्योरमेंट रिफार्म पर हुई स्टेट लेवल वर्कशॉप में कही। वर्कशॉप कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में संपन्न हुई। वर्कशॉप में भारत सरकार के अपर मुख्य सचिव एवं वित्तीय सलाहकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री संजीव शंकर, भारत सरकार में संयुक्त सचिव सुश्री सी. शिखा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्रीमती शमी ने कहा कि गत रबी सीजन में लगभग 9 लाख किसानों से 77 लाख मीट्रिक टन से अधिक गेहूं का उपार्जन किया गया और लगभग 20 हजार करोड़ रूपये किसानों के खाते में अंतरित किये गये। गेहूं के उपार्जन में राज्य सरकार द्वारा 175 रूपये प्रति क्विंटल का बोनस दिया गया है। इसी तरह लगभग 6 लाख 50 हजार किसानों से 43.5 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई है। उपार्जन के

लिये किसानों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आधार नम्बर को भी जोड़ा गया है। उपार्जन केन्द्रों से ही मिलर्स को धान देने का प्रावधान किया गया है। उपार्जन केन्द्रों पर किसानों को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। पीडीएस दुकानों में अनाज ले जाने वाले वाहनों की सघन मॉनिटरिंग की जाती है। प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों को जन पोषण केन्द्र के रूप में विकसित करने की भी योजना है। वर्तमान में इंदौर में यह कार्य शुरू कर दिया गया है। उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न लेने वाले उपभोक्ताओं की ई-केवायसी कराई जा रही है। ई-केवायसी के बाद अपात्र लोगों को बाहर किया गया है और लगभग 5 लाख 70 हजार नये उपभोक्ताओं को सूची में जोड़ा गया है।

वर्कशॉप में भारत सरकार के अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति श्री संजीव शंकर ने आयोजन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्कशॉप में उपस्थित अधिकारी अपने सुझाव जरूर दें। श्री शंकर ने कहा कि उपार्जन की प्रक्रिया को और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, इस संबंध में गहन विमर्श किया जायेगा। भारत सरकार की संयुक्त सचिव पॉलिसी एण्ड एफसीआई सुश्री सी. शिखा ने बिलिंग प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सब्सिडी की जानकारी प्रतिमाह भेजें। उन्होंने मध्यप्रदेश की गुड प्रेक्टिसेस के बारे में भी जानकरी दी और विभाग की कार्यप्रणाली की सराहना की।

जनरल मैनेजर एफसीआई श्री विशेष गढ़पाले ने प्रोक्योरमेंट सेंटर सेल्फ असेसमेंट प्रोग्राम (पीसीएसएपी) के बारे में जानकारी दी। आयुक्त खाद्य श्री कर्मवीर शर्मा ने गेहूं और धान के उपार्जन के संबंध में बनाये गये एक्शन प्लान की जानकारी दी। उन्होंने उपार्जन प्रक्रिया के सरलीकरण के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव भी दिये। एमडी नागरिक आपूर्ति निगम श्री अनुराग वर्मा ने उपार्जन और भंडारण की प्रक्रिया में आने वाली समस्याओं से अवगत कराया। श्री अश्विनी गुप्ता ने फिजिकल वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। अन्य उपस्थित अधिकारियों ने भी महत्वपूर्ण सुझाव दिये।

"एक बगिया मां के नाम" परियोजना

फलोद्यान बगिया विकास में स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने दिखाया विशेष उत्साह

34 हजार से अधिक महिलाओं ने कराया ऐप पर रजिस्ट्रेशन निजी भूमि पर विकसित की जाएगी बगिया

भोपाल : स्व सहायता समूह की महिलाओं को समृद्ध बनाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। नवाचारों के माध्यम से महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अंतर्गत प्रदेश में "एक बगिया मां के नाम" परियोजना शुरू की गई है। इसके अंतर्गत स्व-सहायता समूह की महिलाओं की निजी भूमि पर फलोद्यान की बगिया लगाई जाएगी। फलोद्यान की बगिया लगाने को लेकर समूह की महिलाओं ने विशेष उत्साह का दिखाया है। प्रदेश में निर्धारित लक्ष्य से अधिक 34 हजार 84 महिलाओं ने एक बगिया मां के नाम ऐप पर पंजीयन कराया है। परियोजना के अंतर्गत सरकार हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए कटीले तार की फेंसिंग और सिंचाई के लिए 50 हजार लीटर का जल कुंड बनाने के लिए राशि प्रदान कर रही है। योजनान्तर्गत प्रदेश में फलदार पौधे लगाने का कार्य भी शुरू हो गया है।

MPSEDC ने किया ऐप का निर्माण

एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने वाली स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का चयन एक बगिया मां के नाम ऐप से किया जा रहा है। ऐप का निर्माण मनरेगा परिषद द्वारा MPSEDC के माध्यम से कराया गया है। अन्य किसी माध्यम से हितग्राही का चयन नहीं किया जाएगा। चयनित महिला हितग्राही के नाम पर भूमि नहीं होने की दशा में उस महिला के पति-पिता-ससुर-पुत्र की भूमि पर उनकी सहमति के आधार पर पौधरोपण किया जा सकेगा।

पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से किया जा रहा पौधरोपण

प्रदेश में पहली बार अत्याधुनिक तकनीक से पौधरोपण का कार्य किया जा रहा है। इसके लिए सिपरी सॉफ्टवेयर की मदद ली जा रही है। इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से पौधरोपण के लिए जमीन का चयन वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से किया गया है। जमीन चिन्हित होने के बाद सॉफ्टवेयर की मदद से ही भूमि का परीक्षण किया गया है। जलवायु के साथ ही किस जमीन पर कौन सा फलदार पौधा उपयोगी है, पौधा कब और किस समय लगाया जाएगा, पौधों की सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी कहाँ पर उपलब्ध है, यह सब वैज्ञानिक पद्धति (सिपरी सॉफ्टवेयर) के माध्यम से पता लगाया जा रहा है। जमीन के उपयोगी नहीं पाए जाने पर पौधरोपण का कार्य नहीं होगा। पौधरोपण का कार्य बेहतर ढंग से हो इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।

"एक बगिया माँ के नाम'' परियोजना अंतर्गत प्रदेश की 31 हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को लाभ मिलेगा। इनकी निजी जमीन पर 30 लाख से अधिक फलदार पौधे लगाएं जाएंगे, जो समूह की महिलाओं की आर्थिक समृद्धि का आधार बनेंगे।

हर एक ब्लॉक में 100 हितग्राहियों का किया जा रहा चयन

एक बगिया मां के नाम परियोजना अंतर्गत प्रत्येक ब्लॉक में न्यूनतम 100 हितग्राहियों का चयन किया जा रहा है। चयनित हुई समूह की पात्र महिलाओं को बाकायदा प्रशिक्षित किया जाएगा। यह प्रशिक्षण महिलाओं को वर्ष में दो बार दिया जाएगा।

न्यूनतम 0.5, अधिकतम 1 एकड़ जमीन होना अनिवार्य

एक बगिया मां के नाम परियोजना का लाभ लेने के लिए चयनित हुई समूह की महिला के पास बगिया लगाने के लिए भूमि की सीमा भी निर्धारित की गई है। चयनित महिला के पास न्यूनतम 0.5 या अधिकतम एक एकड़ जमीन होना अनिवार्य है।

प्रति 25 एकड़ पर 1 'कृषि सखी' की होगी तैनाती

फलोद्यान की बगिया लगाने के लिए चयनित हितग्राहियों की सहायता के लिए कृषि सखी की तैनाती की जाएगी। ये कृषि सखी हितग्राहियों को खाद, पानी, कीटों की रोकथाम, जैविक खाद, जैविक कीटनाशक तैयार करने और अंतरवर्तीय फसलों की खेती के बारे में जानकारी प्रदान करेंगी। प्रत्येक 25 एकड़ पर एक कृषि सखी की तैनाती की जाएगी।

ड्रोन-सैटेलाइट इमेज और डैशबोर्ड से निगरानी

पौधरोपण का कार्य सही ढंग से हो रहा है या नहीं, पौधे कहाँ लगे हैं, कहाँ नहीं लगे, इसकी ड्रोन-सैटेलाइट इमेज से बकायदा निगरानी भी की जाएगी। साथ ही पर्यवेक्षण के लिए अलग से एक डैशबोर्ड भी बनाया गया है। प्रदर्शन के आधार पर प्रथम 3 जिले, 10 जनपद पंचायत व 25 ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

हितग्राहियों के चयन में टॉप 5 जिले

एक बगिया मां के नाम परियोजना के लिए हितग्राहियों के चयन में प्रदेश के 5 जिले सिंगरौली, देवास, खंडवा, निवाड़ी और टीकमगढ़ अग्रणी हैं।

दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध-उत्पादों की बेहतर मार्केटिंग जरूरी : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का लाभ गोशाला प्रबंधन और गोवंश के स्वास्थ्य में भी लिया जाए

जहां दुग्ध संघ की पहुंच सीमित है, वहां निजी दुग्ध व्यवसायियों को किया जाए प्रोत्साहित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने की प्रदेश के दुग्ध संघों की गतिविधियों की समीक्षा

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के साथ दुग्ध उत्पादों की बेहतर ब्राडिंग, गोवंश की समुचित देखभाल, वेटनरी क्षेत्र में आवश्यक प्रशिक्षण और उन्नत अधोसंरचना स्थापित करने में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की विशेषज्ञता का हरसंभव लाभ लिया जाए। वर्ष 2030 तक प्रदेश के 26 हजार गांवों तक डेयरी नैटवर्क का विस्तार सुनिश्चित किया जाना है। इससे 52 लाख किलोग्राम दुग्ध संकलन होगा। बढ़े हुए दुग्ध संकलन का समुचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए आधुनिकतम दुग्ध प्रसंस्करण अवसंरचना विकसित की जाए। प्रदेश में निर्मित होने वाले दुग्ध उत्पादों की राष्ट्रीय स्तर पर ब्राडिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और प्रदेश के दुग्ध संघों की गतिविधियों के संबंध में मंत्रालय में हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वैटनरी कॉउंसिल ऑफ इंडिया के सहयोग से प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में वैटनरी के कोर्स संचालित किए जाएं। उन्होंने नगरीयनिकायों की बड़ी गो-शालाओं के उन्नयन और प्रबंधन में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सहयोग लेने की आवश्यकता भी बताई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सभी दुग्ध संघों में एक समान उत्पाद निर्माण सुनिश्चित करने के लिए स्टेण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर अपनाना आवश्यक है। दुग्ध उत्पादकों को दुध-मूल्य के नियमित और समय पर भुगतान की व्यवस्था की नियमित मॉनीटरिंग हो। जिन क्षेत्रों में दुग्ध संघ की पहुंच सीमित है, वहां निजी दुग्ध व्यवसायियों को अद्यतन तकनीक का आवश्यक प्रशिक्षण उपलब्ध कराकर दुग्ध व्यवसाय को प्रोत्साहित और सशक्त किया जाए। प्रदेश के दुग्ध संघ, मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन और मध्यप्रदेश कृषि उद्योग निगम में बेहतर समन्वय सुनिश्चित हो।

बैठक में जानकारी दी गई कि सम्पूर्ण डेयरी चैन का डिजिटाइजेशन करने के लिए दुग्ध संघों में प्रक्रिया आरंभ की गई है। दुग्ध संकलन के लिए इंदौर दुग्ध संघ द्वारा मोबाइल एप का उपयोग आरंभ किया गया है, जिससे दुग्ध उत्पादकों को उनके द्वारा प्रदाय किए गए दूध की मात्रा, गुणवत्ता और मूल्य की जानकारी तत्काल प्राप्त होती है। भोपाल दुग्ध संघ द्वारा शहरी उपभोक्ताओं को दूध की गुणवत्ता की जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 'दूध का दूध-पानी का पानी' अभियान आरंभ किया गया है। भोपाल दुग्ध संघ ने 'सांची भात योजना' भी आरंभ की है, जिसमें सहकारी समितियों के सदस्यों की बेटियों के विवाह के अवसर पर दुग्ध संघ की ओर से 11 हजार रूपए और वस्त्र, भात के रूप में प्रदान किए जाएंगे। उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा पशुधन स्वास्थ्य में सुधार के लिए विशेष अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री उमाकांत उमराव, चेयरमैन राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड डॉ. मीनेष शाह, वेटनरी कॉउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉ. उमेश शर्मा सहित पदाधिकारी उपस्थित थे।

अपेक्स बैंक की 61 वीं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न

बैंक ने वित्तीय 2024-25 में रू.139.04 करोड़ का शुद्ध लाभ कमाया

भोपाल, अपेक्स बैंक की 61 वीं वार्षिक साधारण सभा अपेक्स बैंक में समन्वय भवन के सभागार में म.प्र.शासन के प्रमुख सचिव, सहकारिता एवं अपेक्स बैंक के प्रशासक श्री डी.पी.आहूजा की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक के आरंभ में अपेक्स बैंक के प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने बैंक के प्रशासक श्री डी.पी.आहूजा, आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक श्री मनोज पुष्प एवं बैंक के पूर्व प्रबंध संचालक श्री प्रदीप नीखरा का पुष्प-गुच्छ से स्वागत किया।

श्री गुप्ता ने बैठक में प्रशासक महोदय के अभिभाषण का वाचन करते हुये बैंक की वित्तीय स्थिति से सभी सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा कि समग्र प्रयासों एवं समयबद्ध कार्ययोजना के क्रियान्वयन के फलस्वरूप अपेक्स बैंक द्वारा इस वर्ष अब तक का अधिकतम शुद्ध लाभ रू.139.04 करोड़ का अर्जित किया है। इसलिये बैंक ने अब अपने अंशधारियों को 4 प्रतिशत की दर से लाभांश देने का भी निर्णय लिया है।

उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वर्ष 2024-25 के आय-व्यय के साथ वर्ष 2025-26 के बजट को बैठक में अनुमोदित किया गया। इस वर्ष अपेक्स बैंक को अंकेक्षक ने ''ए'' ग्रेड प्रदान किया है तथा अपेक्स बैंक में इस वर्ष 23 सहायक प्रबंधक, 95 संवर्ग अधिकारियों की आईबीपीएस के माध्यम से भर्ती प्रक्रियाधीन है, जबकि 54 बैंकिंग सहायकों की भर्ती की गई है। इसी प्रकार प्रदेश के 38 जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों में अधिकारी वर्ग के 326, बैंकिंग सहायक वर्ग के 1040 एवं समिति प्रबंधक वर्ग के 839 अर्थात् 2205 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी प्रक्रियाधीन है।

उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की त्रि-स्तरीय सहकारी साख संरचना को मजबूत, सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में केन्द्र प्रायोजित पैक्स कम्प्यूटराईजेषन योजनान्तर्गत प्रदेश की 4536 पैक्स में हार्डवेयर इंस्टाल कर दिये गये हैं एवं 4534 पैक्स साफ्टवेयर पर आन बोर्ड हो चुकी हैं। पैक्स रियल टाईम साफ्टवेयर पर कार्य कर सकें, इसकी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, इससे पैक्स की कार्यप्रणाली और सेवाओं में पारदर्षिता आयी है और जनसामान्य में पैक्स के प्रति विश्वास बढ़ा है। इसी प्रकार पैक्स सदस्यों को उनके खातों के संव्यवहारों की सूचना एस.एम.एस. के द्वारा भेजने वाला प्रथम राज्य मध्य-प्रदेश बन गया है।

अन्त में प्रबंध संचालक श्री मनोज गुप्ता ने प्रदेश के मा.मुख्यमंत्री जी, सहकारिता मंत्री जी, कृषि उत्पादन आयुक्त, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, नेफेस्कॉब, सहकारिता, कृषि एवं खाद्य व नागरिक आपूर्ति विभाग के साथ उपस्थित प्रतिनिधियों, शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालकों का आभार व्यक्त किया। बैठक का संचालन उप महाप्रबंधक श्री के.टी.सज्जन ने किया।

बैठक में नाबार्ड की मुख्य महाप्रबंधक श्रीमती सी.सरस्वती, अपेक्स बैंक के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारीगण श्रीमती अरूणा दुबे, श्री अरूण मिश्र, श्री अरविंद बौद्ध, शीर्ष सहकारी संस्थाओं के प्रबंध संचालक सर्वश्री रितुराज रंजन, महेन्द्र दीक्षित, श्री आर.एस. विश्वकर्मा, अपेक्स बैंक के प्रबंधक श्री करूण यादव, श्री विवेक मलिक, श्री समीर सक्सेना, श्री अजय देवड़ा, आर.वह.एम.पिल्लई के साथ सभी शीर्ष सहकारी संस्थाओं/अपेक्स बैंक के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित हुए

मध्यप्रदेश को बनायेंगे मिल्क केपिटल : मुख्यमंत्री

दुग्ध उत्पादन के जरिए बढ़ायेंगे पशुपालकों की आय, गाय का दूध भी खरीदेगी सरकार

किसान खेती के साथ पशुपालन कर बढ़ाए अपनी आमदनी

दुग्ध उत्पादन को राज्य सरकार दे रही है बढ़ावा

किसानों को सोलर पम्प देकर बिजली बिल से दिलाई जायेगी मुक्ति

भोपाल :मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाना हमारी प्राथमिकता है। आज प्रदेश का हर कोना विकास कार्यों से सज-संवर रहा है। हम प्रदेश के किसानों और पशुपालकों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। दुग्ध उत्पादन में तेजी लाकर हम वर्ष 2028 तक मध्यप्रदेश को मिल्क केपिटल बनाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिर्फ भैंस का नहीं, हमारी सरकार अब गाय का दूध भी खरीदेगी। हम गाय के दूध की खरीदी की कीमत भी ज्यादा देंगे। डॉ. भीमराव अंबेडकर कामधेनु योजना के जरिए हमने तय किया है कि 25 गाय और 42 लाख रुपये तक की गौशाला यूनिट स्थापित करने पर दूध और अन्य उत्पाद तो पशुपालक के होंगे, सरकार पशुपालक को 10 लाख रुपये प्रोत्साहन अनुदान के रूप में देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ी गौशालाओं के निर्माण पर सरकार निवेश लागत की 25 प्रतिशत तक की निवेश राशि अनुदान के रुप में माफ करेगी।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने क्षेत्रीय ग्रामीणों की सुविधा के लिए प्रस्तावित 113 करोड़ रुपये की पेयजल योजना और मोरकुंडवा सिंचाई योजना को भी मंजूरी दी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि किसानों के लिए हमारी सरकार बहुत सारी सौगातें लेकर आई है। पार्वती-काली सिंध-चंबल राष्ट्रीय नदी जोड़ो परियोजना से हम रतलाम जिले के एक-एक गांव और खेत तक पानी पहुंचायेंगे। उन्होंने कहा कि सभी किसानों को सोलर पॉवर पंप देंगे। इससे किसान अपने खेतों में सिंचाई के लिए खुद बिजली पैदा करेंगे। सोलर पंप के जरिए हम किसानों को बिजली बिल से हमेशा के लिए मुक्ति दिला देंगे।

डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन, कढ़ाई क्राफ्ट प्रशिक्षण प्रारंभ

भोपाल। कार्यालय विकास आयुक्त, हस्तशिल्प, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार की वृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास योजना (CHCDS) के अंतर्गत डिज़ाइन एवं तकनीकी विकास कार्यशाला का आयोजन मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ मर्यादित द्वारा किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम13 अगस्त 2025से12 अक्टूबर 2025तकCFC सेंटर, त्रिलंगा शाहपुरा, भोपालमें आयोजित किया जा रहा है।

कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर शिवाऔर डिज़ाइनर देविका दभाड़े द्वारा कढ़ाई क्राफ्ट के प्रशिक्षण प्रदान किए जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण में 30 महिला शिल्पियों को रोज़ाना रु.300के मानदेय पर 2 महीने के लिए कुल रु.15,000 प्रति शिल्पी प्रदान किए जाएंगे। शिल्पियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक प्रणालीके आधार पर मान्य होगी।

13 अगस्त 2025 को इस कार्यशाला का निरीक्षण हस्तशिल्प सेवा केन्द्र भोपाल के सहायक निदेशक, श्री नरसिंह सेनी ने किया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य:

- शिल्पियों को आधुनिक तकनीक, डिज़ाइन नवाचार और विपणन से जोड़ना।
- उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होना।
- उत्पादन गुणवत्ता सुधार, पैकेजिंग और ऑनलाइन विपणन से संबंधित व्यावहारिक जानकारी प्रदान करना।

मुख्य गतिविधियाँ:

- विशेषज्ञों द्वारा उत्पादन तकनीक और गुणवत्ता सुधार का प्रशिक्षण।
- पैकेजिंग एवं ऑनलाइन विपणन के व्यावहारिक अभ्यास।
- शिल्पियों को प्रतिस्पर्धी बाजार में अपने उत्पाद सफलतापूर्वक प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शन।

कार्यशाला में शामिल शिल्पियों ने इसे अत्यंत उपयोगी बताया। उनका कहना है कि इससे उन्हें अपनी आजीविका में सुधार करने और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में नई ऊर्जा मिली है।

किसानों की खुशहाली व बेहतरी के लिये सरकार ने उठाए प्रभावी कदम : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि किसानों की बेहतरी एवं खुशहाली के लिये राज्य सरकार ने प्रभावी कदम उठाए हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, बिजली के बिल से बचाने के लिये कृषि सोलर पंप पर बड़ा अनुदान, कृषि आधारित उद्योगों को विशेष बढ़ावा और पशुपालन व डेयरी के लिये अनुदान सहित किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार तमाम सुविधाएँ मुहैया करा रहीं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर में बलराम जयंती पर आयोजित हुए किसान सम्मान समारोह को भोपाल शासकीय विमानतल से वर्चुअल संबोधित कर रहे थे। उन्होंने इस अवसर पर सभी को कृषि के देवता हलधर भगवान बलराम जयंती की बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। साथ ही आयोजन करने के लिये नंदलाल बाल कल्याण समिति को साधुवाद दिया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि पिछले सवा साल के भीतर प्रदेश में 7 लाख हैक्टेयर से अधिक सिंचाई रकबा बढ़ा है, जबकि वर्ष 2003 में प्रदेश में मात्र लगभग साढ़े 7 लाख हैक्टेयर में सिंचाई होती थी। इस प्रकार आजादी के बाद प्रदेश में जितना सिंचाई का रकबा था, उतनी सिंचाई सुविधा पिछले सवा साल में सरकार ने उपलब्ध करा दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2003 के बाद कुल मिलाकर 44 लाख हैक्टेयर सिंचाई का रकबा बढ़ाया गया है। इसमें लगातार बढ़ोत्तरी जारी है। इसी क्रम में केन-बेतवा और पार्वती–काली सिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना से बुंदेलखंड और ग्वालियर-चंबल संभाग सहित प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में सिंचाई सुविधाओं का क्रांतिकारी विस्तार हो रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि खेती में कम लागत आए, इसके लिये सरकार किसानों को तमाम सुविधाएँ मुहैया करा रही है। सरकार द्वारा किसानों को बिजली के बड़े बिल से बचाने के लिये 10 व 5 हॉर्स पॉवर के सोलर पंप पर 90 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा किसानों को खेती के लिये सरकार बिना ब्याज के कृषि ऋण उपलब्ध करा रही है। साथ ही इस साल सरकार ने देश में सबसे अधिक समर्थन मूल्य 2600 रूपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूँ की खरीदी की है। आने वाले साल में इसमें और बढ़ोत्तरी की जायेगी।

बीहड़ों में लगाई जायेगी नेपियर घास और उद्योग भी होंगे विकसित

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार द्वारा बीहड़ों में नेपियर घास लगवाई जायेगी। साथ ही कृषि आधारित उद्योग विकसित करने के प्रयास भी होंगे। किसानों को उन्नत कृषि तकनीक व कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिये सरकार व्यापक स्तर पर किसान मेलों का आयोजन भी करा रही है। इसी क्रम में जल्द ही मुरैना में वृहद किसान मेला आयोजित होगा, इससे ग्वालियर-चंबल अंचल के किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने ग्वालियर जिले में सुपर सीडर की बड़े पैमाने पर बोवनी एवं ड्रोन दीदियों के प्रशिक्षण की सराहना की। साथ ही कहा किसानों की खुशहाली के लिये प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में दोनों सरकारें लगातार काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर प्रदेश सरकार द्वारा भी मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है। इन दोनों योजनाओं से प्रत्येक किसान के खाते में हर साल 10 हजार रूपए पहुँच रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सरकार कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने की कड़ी में दालों से टैक्स कम कर दाल कारखानों को विशेष प्रोत्साहन दे रही है। उन्होंने दुग्ध उत्पादन में बढ़ोत्तरी एवं नरवाई प्रबंधन के लिये सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रोत्साहन की जानकारी भी दी।

किसान खुशहाल होंगे तो देश भी खुशहाल होगा : कृषि मंत्री श्री कंषाना

कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री श्री ऐदल सिंह कंषाना ने कहा कि किसान खुशहाल होगा तो देश भी खुशहाल होगा। इसी भाव के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में केन्द्र व राज्य सरकार किसानों के हित में काम कर रहीं हैं। उन्होंने कहा प्रदेश में सिंचाई रकबे में क्रांतिकारी विस्तार हुआ है। श्री कंषाना ने इस अवसर पर भरोसा दिलाया कि सरकार प्रदेश के किसी भी जिले व तहसील में खाद की कमी नहीं आने देगी। खाद की कमी की शिकायत आने पर 12 घंटे के भीतर खाद की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी।

भारत में सहकारी बैंकों की स्थिति सशक्त और समृद्ध सहकारी बैंकिंग प्रणाली

दिल्ली, भारत में सहकारी बैंकों का नेटवर्क देश की ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (NABARD) की निगरानी में कार्यरत सहकारी बैंक किसानों, छोटे उद्यमियों और ग्रामीण वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं।

वर्तमान में भारत में कुल1,457 शहरी सहकारी बैंक, 34 राज्य सहकारी बैंक (STCB), 351 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB)औरएक औद्योगिक सहकारी बैंक (तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक)कार्यरत हैं। यह देश की सहकारी प्रणाली की मजबूती और व्यापक पहुँच को दर्शाता है।

ऋण वितरण में उल्लेखनीय वृद्धि

सहकारी बैंकों के बकाया ऋण में 2020 से 2025 के बीच लगातार वृद्धि हुई है। शहरी सहकारी बैंक का कुल ऋण रु.3,05,183 करोड़ से बढ़कर रु.3,68,574 करोड़ हो गया। राज्य सहकारी बैंक (STCB) का ऋण रु.1,99,942 करोड़ से बढ़कर रु.3,19,085 करोड़ हुआ। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (DCCB) का बकाया ऋण 2020 में रु.2,79,272 करोड़ था, जो 2025 में बढ़कर रु.4,44,806 करोड़ तक पहुँच गया।

तमिलनाडु औद्योगिक सहकारी बैंक (TAICO) का ऋण रु.568 करोड़ से बढ़कर रु.669 करोड़ हो गया। इस प्रकार, भारत में कुल सहकारी ऋण 2020 में रु.7,84,965 करोड़ से बढ़कर 2025 में रु.11,33,134 करोड़ तक पहुँच गया। यह लगभग 44% की वृद्धि दर्शाता है, जो देश की सहकारी प्रणाली की मजबूती और वित्तीय समावेशन को उजागर करता है।

तेलंगाना में सहकारी बैंकिंग की सफलता

तेलंगाना राज्य में सहकारी बैंकिंग ने किसानों और छोटे उद्यमियों के लिए आशाजनक परिणाम दिखाए हैं। शहरी सहकारी बैंक का ऋण 2020 में रु.5,031 करोड़ से बढ़कर 2025 में रु.6,805 करोड़ हुआ। राज्य सहकारी बैंक का ऋण रु.6,202 करोड़ से बढ़कर रु.16,975 करोड़ तक पहुँच गया। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक का ऋण रु.8,062 करोड़ से बढ़कर रु.17,467 करोड़ हो गया।

कुल मिलाकर, तेलंगाना में सहकारी बैंकों का ऋण 2020 में रु.19,295 करोड़ से बढ़कर 2025 में रु.41,247 करोड़ हो गया। यह पाँच वर्षों में लगभग दोगुने से अधिक की वृद्धि दर्शाता है और राज्य में कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण को उजागर करता है।

सहकारी बैंकिंग प्रणाली ने न केवल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में आर्थिक विकास का एक मजबूत आधार भी तैयार किया है। RBI और NABARD की सतत निगरानी के तहत यह प्रणाली किसानों, लघु व्यवसायियों और समाज के कमजोर वर्गों के लिए एक सशक्त वित्तीय सहारा बनकर उभरी है।भारत में सहकारी बैंकों की निरंतर वृद्धि और सफलता देश की समृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक सकारात्मक संकेत है।

अपेक्स बैंक में श्री मनोज पुष्प ने किया ध्वजारोहण

भोपाल। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपेक्स बैंक केटी.टी. नगर स्थित मुख्यालयके प्रांगण एवं छठवीं मंजिल की छत परआयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक, सहकारी संस्थायें, मध्यप्रदेश श्री मनोज पुष्पने राष्ट्रीय ध्वज फहराया।

इस अवसर पर बैंक के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। प्रमुख उपस्थितगण इस प्रकार थे:

- उप सचिव सहकारिताश्री मनोज सिन्हा
- पूर्व प्रबंध संचालक एवं प्राचार्य, अपेक्स बैंक ट्रेनिंग कालेजश्री पी.एस. तिवारी
- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारीगण:श्रीमती अरूणा दुबे, श्री अरूण मिश्रा, श्री संजय मोहन भटनागर
- आवास संघ के प्रबंध संचालकश्री आर.एस. विश्वकर्मा
- उप महाप्रबंधकश्री के.टी. सज्जन, प्रबंधकश्री विवेक मलिक, श्रीसमीर सक्सेना, श्रीअजय देवड़ा, उप प्रबंधकश्री एस.के. जैन
- अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी

ध्वजारोहण समारोह के दौरान उपस्थित सभी ने तिरंगे को सलामी दी और स्वतंत्रता दिवस के महत्व तथा देशभक्ति के संदेश को साझा किया।

अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 अन्तर्गत सहकारिता से समृद्धि विषय पर कार्यशाला संपन्न

जबलपुर। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र, कटंगा, जबलपुर में अन्तरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अन्तर्गत युवा वर्ग के लिए सहकारिता से समृद्धि विषय पर एक ज्ञानवर्धक और उपयोगी सहकारी कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें। सहकारी समिति के गठन और विकास को लेकर उत्सुक युवाओं के लिए सहकारिता के माध्यम से रोजगार के विभिन्न संसाधनों पर प्रभावी व्याख्यान दिए गए। केन्द्र के पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक ने विषय विशेषज्ञ के रुप में सहकारिता के विकास के लिए सहकारी नेतृत्व और सहकारी प्रबंधन के समन्वय को आवश्यक बताया । उन्होंने सहकारी समिति के लिए जरूरी कार्यालय प्रबंध और वित्तीय प्रबंध की जानकारी दी । केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही. के. बर्वे ने सहकारिता के सफल संचालन के लिए विक्रय प्रबंधन के अंतर्गत मूल्य निर्धारण नीति के आवश्यक तत्वों के अतिरिक्त सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र की विकासशील गतिविधियों की भी जानकारी दी । प्राचार्य जी ने युवा वर्ग के लिए सहकारी प्रशिक्षण को अत्यंत उपयोगी सिद्ध किया ।

कार्यशाला में केन्द्र के प्रशिक्षक श्री पीयूष राय और श्री जय कुमार दुबे ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रशिक्षक श्री अखलेश उपाध्याय ने किया। आभार प्रदर्शन श्री एन. पी. दुबे द्वारा किया गया ।

सहकारिता में युवाओं की भागीदारी

जबलपुर, म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्या. भोपाल द्वारा संचालित सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अन्तर्गत ओरिएंटेशन प्रोग्राम सहकारिता में युवाओं की भागीदारी विषय पर शासकीय पी.एम. श्री कन्या हायर सेकेण्ड्री स्कूल सालीवाड़ा गौर जबलपुर में कक्षा 11वीं एवं 12वी के छात्र छात्राओं हेतु एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यकम दिनांक 25/08/2025 को आयोजित किया गया।

श्री व्ही.के. बर्वे प्राचार्य, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जबलपुर द्वारा कार्यक्रम आयोजन 'की रूपरेखा अंतर्राष्ट्रीय सहकारी वर्ष 2025 की उपयोगिता सहकारिता का अर्थ, उद्देश्य और महत्व एवं सफल सहकारी संस्थाओं पर चर्चा की श्री यशोवर्धन पाठक पूर्व प्राचार्य द्वारा सहकारिता में युवाओं की भागीदारी विषय पर उदाहरण द्वारा चर्चा की। श्री जय कुमार दुबे एवं श्री अखलेश उपाध्याय द्वारा सहकारी गतिविधियों पर प्रकाश डाला अंत में शाला के व्यायाता श्री अखलेश मिश्रा द्वारा सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम को उपयोगी बताते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम शाला स्तर पर प्रशिक्षण होते रहना चाहिए जिससे नई पीढ़ी के युवा वर्ग सहकारिता को समझ सकें। कार्यक्रम में केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही० के० बर्वे एवं पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक, प्राचार्य श्रीमति आभा बानखेडे, व्याख्याता श्रीमति सरोज रॉय, श्रीमति प्रीति कोरहार, श्री अखलेश मिश्रा, प्रशिक्षक श्री जय दुबे, श्री अखलेश उपाध्याय एवं स्कूल के समस्त स्टाफ की उपस्थिति में कार्यक्रम किया गया। अंत में श्री एन० पी० दुबे लिपिक द्वारा शाला के समस्त स्टाफ का आभार व्यक्त किया गया।

अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 के अंतर्गत सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र कटंगा जबलपुर द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सालीवाड़ा,गौर , जबलपुर में सहकारिता में युवाओं की भागीदारी विषय पर सारगर्भित प्रशिक्षण प्रदान किया गया । इस अवसर पर केन्द्र के प्राचार्य श्री व्ही के बर्वे , पूर्व प्राचार्य श्री यशोवर्धन पाठक,श्री जय कुमार दुबे,श्री अखलेश उपाध्याय ने सहकारिता के विभिन्न विषयों पर प्रभावी व्याख्यान दिया। आभार प्रदर्शन केन्द्र की ओर से श्री एन. पी. दुबे द्वारा किया गया।

तिरंगे के सम्मान में, एकता और गर्व का संगम – भोपाल में भव्य तिरंगा यात्रा

भोपाल, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ, भोपाल मुख्यालय में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार केहर घर तिरंगाअभियान के अंतर्गत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, एकता और देशभक्ति की भावना को और प्रगाढ़ करना है।

तिरंगा यात्रा में भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय केसीएचसीडीएस परियोजनासे जुड़ी महिला प्रतिभागियों ने विशेष रूप से भाग लिया। साथ ही, मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ की विशेषज्ञ संस्था सीड के अधिकारी एवं कर्मचारीगण, भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय भोपाल के स्टाफ तथा अन्य सहकारी कार्यकर्ता भी सक्रिय रूप से शामिल हुए।

इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य सहकारी संघ के प्रबंध संचालक श्री ऋतुराज रंजन, महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह, सहायक निदेशक, विकास आयुक्त हस्तशिल्प सेवा केंद्र भोपाल, भारत सरकार, वस्त्र मंत्रालय, श्री नरसिंह सैनी, संघ लेखा अधिकारी श्रीमती रेखा पिप्पल, सहकारी प्रशिक्षण केंद्र भोपाल के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी तथा संघ के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारीगण यात्रा में शामिल होकर इसे सफल बनाने में सहभागी बने।

महिला प्रतिभागियों ने तिरंगा हाथ में लेकर "तिरंगा अमर रहे", "भारत माता की जय", "वंदे मातरम्" जैसे देशभक्ति के नारों के साथ यात्रा में उत्साह भर दिया। शहर की सड़क पर निकली यह तिरंगा यात्रा राष्ट्रप्रेम, एकता और सम्मान का अद्भुत प्रतीक बनी।

संघ ने सभी नागरिकों से आग्रह किया है कि वे तिरंगा यात्रा में सम्मिलित होकर तिरंगे की शान और देश की आन-बान में अपना योगदान दें। यह केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि हमारे गौरव, स्वतंत्रता और एकता का उत्सव है। तिरंगे की छांव में उठाया गया हर कदम आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा।

हर्ष एवं उल्लास के साथ मनाया स्वतंत्रता दिवस पर्व

भोपाल। मध्यप्रदेश राज्य सहकारी संघ ने अपने मुख्यालय में 79वें स्वतंत्रता दिवस समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाप्रबंधक श्री संजय कुमार सिंह ने की और उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का ध्वजारोहण किया।

अपने उद्बोधन में श्री संजय कुमार सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का उद्देश्य भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और इस दिशा में सहकारिता का योगदान महत्वपूर्ण है। उन्होंने यह भी कहा कि किसान उत्पादक संगठनों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों और संचालन की योजनाओं को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा।

श्री सिंह ने युवाओं को सहकारिता से जोड़ने हेतु नए इंटर्नशिप कार्यक्रम की घोषणा की, जिससे विद्यार्थियों में व्यावसायिक अवसरों का विकास होगा। इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं के लिए कौशल विकास और सहकारी योजनाओं के माध्यम से उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की सक्रिय पहल का भी उल्लेख किया।

कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख अधिकारी और अतिथि:

विशेष अतिथि के रूप में श्री नरसिंह सेनी, सहायक निदेशक, हस्तशिल्प सेवा केन्द्र भोपाल, तथा सीड संस्था के अध्यक्ष श्री मनीष राजपूत और सचिव श्री धर्मेन्द्र राजपूत उपस्थित थे। संघ के वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी—जिनमें लेखाधिकारी श्रीमती रेखा पिप्पल, सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र भोपाल के प्राचार्य श्री गणेश प्रसाद मांझी, पूर्व प्राचार्य श्री ए. के. जोशी, श्री संतोष येडे, डॉ. योगेश नामदेव, श्री रॉबिन सक्सेना, श्री विक्रम मुजुमदार आदि शामिल थे।

साथ ही, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संचालितवृहद हस्तशिल्प क्लस्टर विकास परियोजनाके 60 हस्तशिल्पी भी उपस्थित थे।

सहकारी प्रशिक्षण केन्द्रों में ध्वजारोहण एवं रैली:

- **नौगांव (जिला छतरपुर):**प्राचार्य श्री शिरीष पुरोहित द्वारा ध्वजारोहण। सहकारिता आंदोलन में आजादी की भूमिका पर विशेष प्रकाश। 15 अगस्त को भव्य रैली का आयोजन।
- **इंदौर:**प्राचार्य श्री दिलीप मरमट द्वारा ध्वजारोहण। उपस्थित थे श्रीमती राधा शर्मा, श्रीमती उमा भुमरकर, श्री सुयंश शर्मा, श्री प्रदीप कुमार रायकवर और जिला सहकारी शिक्षा प्रशिक्षक श्री राहुल श्रीवास।
- **जबलपुर:**प्राचार्य श्री विजय कुमार बर्वे द्वारा ध्वजारोहण। उपस्थित थे श्री अखिलेश सिंह, श्री पीयूष राय, श्री जयकुमार दुबे और श्री एन.पी. दुबे।

राज्यभर में स्वतंत्रता दिवस समारोह देशभक्ति और सहकारिता के संदेश के साथ बड़े उत्साह एवं उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर सहकारी संघ ने देशवासियों को एकजुटता, सेवा और विकास के लिए प्रेरित किया।

म.प्र. राज्य सहकारी संघ मर्यादित भोपाल की ओर से प्रकाशक, मुद्रक गणेश प्रसाद मांझी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी मुद्रणालय परिमित, भोपाल से मुद्रित एवं ई-8/77, शाहपुरा भोपाल से प्रकाशित। प्रबंध सम्पादक : ऋतुराज रंजन, संपादक : गणेश प्रसाद मांझी डॉक पंजीयन क्रमांक : म.प्र./भोपाल/357/2021-23 मुद्रित पत्र रजि. नं./आर.एन./13063/1967, फोन : 2926159, 2926160, इस अंक में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं जिनमें संपादकीय सहमति आवश्यक नहीं है।